THE MINISTER OF TEXTILES AND THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) and (b) The Medical Education Review Committee, whose report was placed before the Parliament on the 2nd May, 1986, had made a recommendation for the establishment of an autonomous Medical and Health Education Commission, which would be responsible for coordination, planning and implementation of various medical and health education programme in all branches of health sciences planning, for the development of health manpower, allocation of funds and disbursement of grants to medical and health institutions etc. This recommendation has been accepted, in principle, and action has been initiated in consultation with various organisations and medical education scientists to work out the modalities regarding the setting up of such a Committee.

Ban on Ailing up vacant posts on *ad-hoc* basis

3124. SHRI ASHOK NATH VERMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a ban has been imposed for filling up vacant posts on *ad-hoc* basis ; if so, since when ;

(b) whether these ban orders are applicable to ex-Cadre (non-ministerial) posts or it includes posts under Central Secretariat Services also ; and

(c) what is the number of posts filled up on *ad-hoc* basis in each cadre (classwjse), for ex-cadre/C.S.S. separately in the Ministry of Agriculture, Ministry of Food and Civil Supplies and its attached offices separately during years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) and (b)Revised instructions on ad-hoc appointments have been issued vide Department of Personnel and Training OM No. 28036/8/87-Estt.(D) dated 30-3-88 (copy enclosed) *[See* Appendix CXLIX, Annexure No.' 168]. These instructions do not impose a total ban on filling up of posts on ad-hoc basis. The instructions apply to all posts under the Central Government including posts in the Central Secretariat Service.

(c) Such information is not centrally maintained.

Promotions in Army Ordnance Corps

3125. SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of persons from O.S. Gd. II who have been promoted to O.S. Gd. I in Army Ordnance Corps during the last three years ;

(b) whether the SC/ST candidates have been considered for the said promotion on the basis of their seniority ;

(c) whether the promotions have been made on the reservation policy as being followed in the Central Government Offices, as per the roster points ; and

(d) if not, the reasons therefor and what steps have been taken to clear the backlog ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI) : (a) 19.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) Does not arise in view of reply (b) and (c), above.

दिल्ली नगर निगम द्वारा दवाओं की खरीद में घोटाला

3126. श्री शरद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 दिसम्बर, 1988 के "दैनिक वीर अर्जन" में "दिल्ली नगर निगम द्वारा दवाओं की खरीद में लाखों का घोटाला" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दवाओं की खरीद में लाखों रुपये का घोटाला किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दवाओं की खरीद एक प्राधिकृत खरीद प्रक्रिया के अनुसार की गई है ।

प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाना

3127. श्री शरद यादव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का विचार रखती है;

(ख) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और यह प्रस्ताव किस चरण में है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) वर्ष 1989–90 के दौरान 120 चुनिंदा जिलों में जहां अत्यधिक बेरोजगारी है और पिछड़े हुए हैं, उनमें जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नवीन गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस नए कार्यक्रम से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हरेक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है। इस स्कीम के लिए यह राशि एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. के अन्तर्गत जिसे कि 1–4–1989 से मिला दिया गया है, जिले के लिए उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त होगी। रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी करने के लिए और उत्पादक परिसंपत्तियां सृजित करने के लिए ये राशियां शामिल की जाएंगी और स्थानीय रूप से लाभदायक स्कीमें आरम्भ की जाएंगी ।